The Statesman 18 January, 2017

'Note ban can't stop future black money'

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 17 January

Demonetisation may wipe out the present stock of black money held in cash from the economy, but cannot eliminate the ill-gotten wealth converted into assets such as gold and real estate, Assocham said today.

However, the industry body has suggested measures like lowering stamp duty on property transactions to tackle the menace.

"Invalidating existing high-denomination notes addresses the stock of black money but does little to address future flows. Eliminating such flows will require further reforms like lowering stamp duty on property transactions, electronic registration of real estate, etc," the Assocham study said.

Moreover, it said, indications that most of the scrapped currency has returned to the banking system through right or wrong means do suggest that demonetisation may not even fully wipe out the existing stock of ill-gotten cash.

"To that extent, even our study may turn out to be ambitious if the tax authorities are not able to trace the money laundered through different accounts. Given the resource constraints with the tax authorities, carrying out such an exercise for identification of laundered money may be a herculean task," Assocham secretary-general D S Rawat said. The study pointed out that high denomination currency withdrawal is not without some inherent problems.

Millennium Post 18 January, 2017

Note ban can do little to stop flo[w] of future black money: India Inc

NEW DELHI: Demonetisation may wipe out the present stock of black money held in cash from the economy but cannot eliminate the ill-gotten wealth converted into assets such as gold and real estate, Assocham said on Tuesday.

However, the industry body has suggested measures like lowering stamp duty on property transactions to tackle the menace. "Invalidating existing high-denomination notes addresses the stock of black money but does little to address future flows. Eliminating such flows will require further reforms like lowering stamp duty on property transactions, electronic registration of real estate etc," the Assocham study said.

Moreover, it said, indications that most of the scrapped currency has returned to the banking system through right or wrong means do suggest that demonetisation may not even fully wipe out the existing stock of ill-gotten cash.

"To that extent, even our study may turn out to be ambitious if the tax authorities are not able to trace the money laundered through different accounts. Given the resource constraints with the tax authorities, carrying out such an exercise for identification of laundered money may be a herculean task," Assocham Secretary General D S Rawat said.

The study pointed out that high denomination currency withdrawal is not without some inherent problems.

"It is very difficult to separate black money from white money because distinction is not once-and-for-all. White money used to purchase something becomes black if the shopkeeper does not pay sales tax," the study noted, adding that much of conspicuous consumption is paid for in unaccounted money, which, in the hand of the recipients can again become perfectly legal income.

Ultimately, the problem of undisclosed incomes and wealth has to be tackled at the source, Assocham highlighted. "Government must reduce the opportunity and incentives for unaccounted transactions by narrowing the gap between the market value and the one fixed by the government agencies for different levies like stamp duty etc," Rawat said. PTI

Rashtriya Sahara 18 January, 2017

काले धन पर रोक के लिए स्टांप शुल्क में कमी जरूरी

■ नई दिल्ली।

उद्योग मंडल ने काला धन की समस्या से निपटने के लिए स्टांप शुल्क में कमी और जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रानिक रूप से पंजीकरण जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है।

एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में काला धन के मौजूदा भंडार को निकाला जा सकता है लेकिन गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति को सोना तथा जमीन-जायदाद जैसी संपत्ति में बदलने को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए स्टांप शुल्क में कमी जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है। उद्योग मंडल के अध्ययन में कहा गया है, 'उच्च राशि के नोट को चलन से प्रतिबंधित करने से काला धन के भंडार की समस्या दूर होगी लेकिन भविष्य में प्रवाह पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार के प्रवाह को रोकने के लिए संपत्ति लेन-देन पर स्टांप शुल्क में कमी, जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रानिक रूप से पंजीकरण आदि जैसे उपाय किए जाने की जरूरत होगी।'

एसोचैम की रिपोर्ट

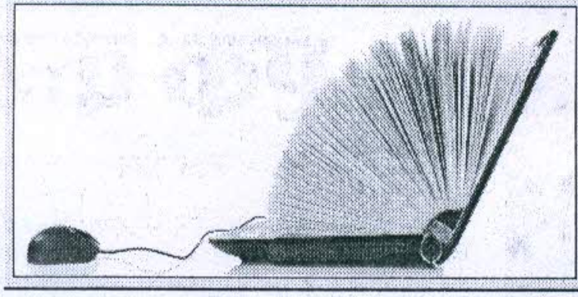

इसके लिए संपत्ति की रजिस्ट्री को डिजिटल किया जाना बेहद जरूरी

नोटबंदी के बाद बंद की गई मुद्रा का पूरा हिस्सा बैंकों में जमा हुआ

नोटबंदी से नहीं दूर की जा सकती काले धन की समस्या

अध्ययन के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि प्रतिबंधित मुद्रा का लगभग पूरा हिस्सा बैंकों में सही या गलत तरीकों से आ गया है। यह बताता है कि बड़े नोटों को चलन से बाहर करने से गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति समाप्त नहीं हो सकती। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा, 'कर अधिकारियों के पास संसाधन संबंधी बाधाओं को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद बनाने की पहचान कठिन कार्य हो सकता है।' ■ भाषा

Amar Ujala **18 January, 2017**

नोटबंदी से नहीं रुकेगा काला धन: एसोचैम

नई दिल्ली। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में पहले से नकदी के रूप में मौजूद काला धन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन यह उस काला धन को समाप्त नहीं कर सकता, जिसे सोने या रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों में बदल लिया गया है। यह बात प्रमुख उद्योग संघ एसोचैम ने मंगलवार को कही। एसोचैम ने काला धन खत्म करने के लिए संपत्ति पर स्टांप शुल्क कम करने जैसे कदमों का सुझाव दिया।

एसोचैम के एक अध्ययन में कहा गया है कि नोटबंदी से मौजूदा काला धन खत्म हो सकता है, लेकिन भविष्य में काला धन बनने की प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती है। प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए और सुधार करने होंगे, जैसे, संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टांप शुल्क कम करना, रियल एस्टेट का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण आदि। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि चलन से हटाए गए अधिकतर नोट सही या गलत तरीके से बैंकिंग प्रणाली में पहुंचने के संकेतों से तो यही पता चलता है कि नोटबंदी से शायद पुराने काले धन को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि काला धन और सफेद धन को अलग कर पाना कठिन है। सफेद धन के भुगतान के बाद यदि विक्रेता बिक्री कर नहीं देता है, तो वही धन काला हो जाता है। एजेंसी

काला धन खत्म करने के लिए और सुधार करने होंगे, जैसे, संपत्ति की खरीद-बिक्री पर स्टांप शुल्क कम करना, रियल एस्टेट का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण, आदि

Jansatta 18 January, 2017

कालेधन पर रोक के लिए जमीन-जायदाद के पंजीकरण का डिजिटलीकरण हो : एसोचेम

नई दिल्ली,17 जनवरी(भाषा)। उद्योग मंडल ने कालाधन की समस्या से निपटने के लिये स्टाम्प शुल्क में कमी और जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रानिक रूप से पंजीकरण जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है।

एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में कालाधन के मौजूदा भंडार को निकाला जा सकता है लेकिन गलत तरीके से कमाई गयी संपत्ति को सोना तथा जमीन-जायदाद जैसी संपत्ति में बदलने को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिये स्टांप शुल्क में कमी जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है। उद्योग मंडल के अध्ययन में कहा गया है- उच्च राशि के नोट को चलन से प्रतिबंधित करने से कालाधन के भंडार की समस्या दूर होगी लेकिन भविष्य में प्रवाह पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार के प्रवाह को रोकने के लिये संपत्ति लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क में कमी, जमीन-जायदाद का इलेक्ट्रानिक रूप से पंजीकरण आदि जैसे उपाय किए जाने की जरूरत होगी।

अध्ययन के अनुसार ऐसे संकेत हैं कि प्रतिबंधित मुद्रा का लगभग पूरा हिस्सा बैंकों में सही या गलत तरीकों से आ गया है। यह बताता है कि बड़े नोटों को चलन से बाहर करने से गलत तरीके से कमाई गयी संपत्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा- कर अधिकारियों के पास संसाधन संबंधी बाधाओं को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद बनाने की पहचान कठिन कार्य हो सकता है।

Dainik Bhaskar 18 January, 2017

नोटबंदी से कालेधन पर कोई खास असर नहीं : एसोचैम

नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में नकदी के रूप में मौजूद कालाधन भले खत्म हो गया हो, लेकिन रियल स्टेट और गोल्ड के रूप में बदला गया कालाधन खत्म नहीं हो सकता। उद्योग संगठन एसोचैम ने यह दावा अपनी एक रिपोर्ट में किया है। हालांकि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सरकार को प्रॉपर्टी के लेनदेन पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने जैसे उपाय करने चाहिए। रियल स्टेट में हर लेनदेन को पारदर्शी बनाने प्रयास होने चाहिए। ऐसा कर सरकार बहुत हद तक कालेधन पर लगाम लगा सकती है। एसोचैम के मुताबिक, रियल स्टेट, कमोडिटी मार्केट और बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार को जल्द से जल्द कड़े कानून और टेक्नोलॉजी का समावेश करना होगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरकार बेनामी डील्स का खुलासा कर सकती है। ऐसा कर ब्लैकमनी पर धीरे-धीरे लगाम लगाई जा सकती है।